(ङ) "कपार्ट" द्वारा इसके लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) 1992-93 एवं 1993-94 के दौरान कपार्ट ने राजकोट के किसी भी स्वैच्छिक संगठन को कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी है। वर्ष 1994-95 के दौरान राजकोट के एक स्वैच्छिक एजेंसी को 14,78,080 रुपये की स्वीकृति दी गयी है। इसमें से 7,72,728/- रुपये की धनराशि रिलीज की गई है।

(ख) कापार्ट उन स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिन्होंने सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या संबंधित स्टेट एक्ट के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में अथवा इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1882 या चेरिटेबल एंड रेलिजियन ट्रस्ट एक्ट, 1920 के अन्तर्गत ट्रस्ट के रूप में ग्रामीण विकास परियोजनाओं को चलाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कम से कम तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त कर लिया है। वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते वक्त अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रस्ताव की तकनीकी ग्राह्यता और आर्थिक व्यवहार्यता और स्वैच्छिक संगठन की प्रशासनिक क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

World Bank Assistance under National Agricultural Extension Project

543. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the names of the projects for which the Government of Gujarat has received financial assistance from the World Bank under the National Agricultural Extension Project indicating the amount received for the purpose during the last three years, year-wise and district-wise;

(b) the details of the work performed with the said assistance during the above said period;

(c) whether agricultural production in the State has increased as a result of the National Agricultural Extension Project; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN): The World Bank assisted National Agricultural Extension Project-II was in operation in the State from 1985 to 1993 for a total cost of Rs. 278.87 million. The assistance under the project was not direct but on reimbursement basis and the total amount of credit disbursed accounted for Rs. 227.85 million by the project closing date.

Under another World Bank assisted project (National Agricultural Extension Project-III), an Advance Training Centre on Groundnut Production Technology has been established at Gujarat Agricultural University, Junagarh with the total cost of Rs. 35.00 lakh for providing training to the Subject-Matter Specialists. The project has since been closed by March, 1995.

(b) The project provided for strengthening of extension services in the State by way of positioning of incremental extension staff at various levels, improved research extension linkages, providing training, information support, mobility for extension functionaries and official and residential civil works. The details of the work performed during the period under various project components is given in Statement (*see* below).

(c) and (d) Agricultural production is a function of several factors such as quality seeds, fertilizers/plant protection, irrigation, weather conditions, etc. and extension is one of the contributory factors, and increases in production cannot directly be attributed to extension efforts alone.

Statement

Details of the work performed under the world bank assisted national agricultural extension project in Gujarat

S. No.	Project Component	Target for the project period	Achievement by project closing date
1.	Positioning of incremental staff	1124	1124
2.	Civil Works	1355	259
3.	Vehicle procurement	211	204
4.	Training Programmes	32503	24414

रोजगार गारन्टी योजना

544. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार गारन्टी योजना किस वर्ष चालू की गई है;

(ख) रोजगार गारन्टी योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस समय यह योजना किन-किन राज्यों में लागू की जा रही है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना की वर्ष-वार और राज्य-वार क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलासबाबूराव मुत्तेमवार):

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कोई भी रोजगार गारंटी योजना नहीं चलाई जा रही है। हालांकि एक सुनिश्चित रोजगार योजना 2.10.1993 को शुरू की गई थी।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य गैर कृषि मौसम में शारीरिक रूप से सक्षम उन सभी व्यस्कों को आयोपार्जक रोजगार प्रदान करना है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है और जो काम के इच्छुक हैं परन्तु जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। यह काम उन्हें उस अवधि के दौरान खेत में या अन्य सहायक कार्यों में अथवा सामान्य योजना/गैर योजना कार्यों के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है। इसका द्वितीयक उद्देश्य स्थायी रोजगार एवं विकास के लिए आर्थिक ढांचे और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। इस समय निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सुनिश्चित रोजगार योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है:—आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पं. बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव एवं लक्षद्वीप।

(ग) इस योजना के वर्षवार एवं राज्यवार उपलब्धियों को नीचे विवरण में देखा जा सकता है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत भौतिक प्रगति

लाख श्रमदिन

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सृजित श्रमदिन				कार्यों की संख्या		
		अनु॰ जाति	अनु॰ जन-जाति	अन्य	कुल	महिलाएं	पूरे किए गये	प्रगति पर
1.	आंध्र प्रदेश	NR	NR	NR	62.42	NR	1336	3769
2.	अरुणाचल प्रदेश	NIL	3.61	0.03	3.64	1.33	156	76